India (RBI) the benefits of fertiliser and electricity subsidies are not reaching the small and medium farmers in the country;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what steps Government propose to take to help the small and medium farmers in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FINANCE AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) and (b) Two studies namely Agricultural Policy in India—Context, Issues and Instruments, and Farm Input Subsidies and State Finances (a case study of Maharashtra and Uttar Pradesh) were done by the Reserve Bank of India. However, both these studies are silent about the benefits of fertiliser and electricity subsidies to the small and medium farmers in the country.

(c) In order to provide some relief to the farmers including the small and medium, the Government have allocated Rs. 756 crores during 1993-94 to provide the decontrolled fertilisers at subsidised rates.

महिला कल्याण हेतु बजट आबंटन में कटौती

1895. **श्री राम नरेश यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक की शर्तों के अंतर्गत महिलाओं की उपेक्षा की गई है जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि महिलाओं से संबंधित योजनाओं संबंधी परिव्यय में कटौती की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो महिलाओं से संबंधित योजनाओं के परिव्यय में कटौती करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1993-94 के बजट आबंटन में "महिला कल्याण" मद के अंतर्गत 49.36 प्रतिशत कटौती की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) 1992-93 के लिए संशोधित अनुमानों में 112.33 करोड़ रु० के बजट आवंटन में 24.50 करोड़ रु० अतिरिक्त लाभभोगियों हेतु अनुपूरक पौष्टिकता की योजना के लिए शामिल हैं जो 1993-94 से राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को हस्तांतरित कर दिये गये हैं । इसको छोड़कर संशोधित अनुमान 87.83 करोड़ रुपये है । इसमें राष्ट्रीय महिला कृण कोष के समूहों के लिए एक बार अंशदान दिये जाने के लिए 31 करोड़ रु० की व्यवस्था शामिल है। महिलाओं के कल्याण की अन्य योजनाओं के लिए संशोधित अनुमान 56.83 करोड़ रु० है। इसके मुकाबले महिलाओं के कल्याण के लिए 1993-94 का बजट अनुमान 62.97 करोड़ रु० है।

उत्तर प्रदेश में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निवेशित राशि

1896. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में उत्तर प्रदेश में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 207 रुपए राष्ट्रीय औसत की तुलना में औसत 200 रुपए की राशि का निवेश किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) उत्तर प्रदेश में निवेश की राशि को राष्ट्रीय औसत के बराबर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) राज्य सरकार प्रतिभूतियों तथा अन्य राज्य स्तरीय निकायों जैसे राज्य बिजली बोर्ड, राज्य वित्तीय निगम, आदि में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निवेश किए जाते हैं । सातवीं पंच वर्षीय योजना (मार्च 1990) के अंत की स्थिति के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों का प्रतिव्यक्ति निवेश, अखिल भारतीय 249 रुपए के औसत की तुलना में उत्तर प्रदेश राज्य में 207 रुपए का था । जहां तक बैंक ऋण के संवितरण का संबंध है, अखिल भारतीय 1342 रुपए के औसत की तुलना में, मार्च 1990 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति बैंक ऋण 605 रुपए था । ऋण का संवितरण, क्षेत्र की ऋण खपाने की क्षमता पर निर्भर रहता है जो बिजली विपणन नेटवर्क संचार आदि जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता से संबंधित है । राज्यों में ऋण संवितरण से संबंधित मुद्दों पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में नियमित रूप से चर्चाएं की जाती हैं । उत्तर प्रदेश राज्य के लिए, राज्य में ऋण संवितरण को सुधारने हेतु उपाय सुझाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की गई है ।

Loans advanced by Banks situated in New York

1897. SHRI GURUDAS DAS GUPTA:

SHRI N. GIRI PRASAD:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that (1) State Bank of India and (2) Bank of India offices at New York gave loans of 1.4 million and 5.9 million respectively and whether any arrests have been made in New York in this connection;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) whether any enquiry has been made and action taken against those bank staff who are involved?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) and (b) It is presumed that the question refers to reports which appeared in certain sections of the Press about the loans raised by one Shri Ponnapula S. Prasad. State Bank of India, New York Branch had sanctioned a loan of US $ 1.40 million to a Company owned by Shri Prasad. Bank of India, New York Branch had sanctioned a loan of US $ 4.00 million to another company owned by Shri Prasad. Bank of India had also sanctioned a loan of US $ 1.90 million to a Company in which Shri Murli Krishna, brother of said Shri Prasad, was a Director. Shri Murli Krishna was arrested and released on 9-7-93. It will not be possible to give further details of these loans under the Statutes governing public sector banks.

(c) Both the banks, namely, State Bank of India and Bank of India, are taking necessary action against the concerned officials for their lapses.

Air Travel Tax Outstanding against Air Taxi Operators

1898. SHRI RAMACHANDRAN PILLAI:

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the amounts of Air Travel Taxes realised from different private airlines during the year 1992-93;

(b) the arrears of tax outstanding if any, from them the amount of arrears and against whom the arrears are outstanding; and

(c) the steps taken to realise the arrears?